भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

जून, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **18** जून, **2021** को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कोविड से संबंधित उपायों के बारे में वास्तविक समय में डेटा/सूचना की उपलब्धता और वहाँ प्रभावी कोविड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया । यह डैशबोर्ड ग्रामीण स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) द्वारा किये जा रहे कोविड कन्टेनमेंट, जागरुकता एवं उपचार उपायों, ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड जागरुकता पर आईईसी गतिविधियां, नामांकित स्वयंसेवकों, नामांकित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, आइसोलेशन केंद्रों वाली ग्राम पंचायतों आदि उपायों के लिए कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को कैप्चर करता है। ।यह डैशबोर्ड केंद्र/राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्थानीय नीतिगत प्रयासों की योजना बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधन प्रयासों के अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा। इस कार्यक्रम के दौरान, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने राहत उपायों के रूप में उनके द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों

और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान, केंद्रीय / राज्य निधि आदि के उपयोग के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। राज्यों ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोविड डैशबोर्ड के शुभारंभ का स्वागत किया और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के प्रावधानों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और सराहना की।

2. राज्यों द्वारा अब तक ऑडिट ऑनलाइन के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न पहलुओं और उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए श्री आर.जी. विश्वनाथन, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2021 को एक चर्चात्मक वर्चुअल सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभागों/राज्यों के वित्त विभागों, सभी राज्यों के एजी/पीएजी के वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा आदि ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान, प्रमुख राज्यों- तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात द्वारा ऑडिट ऑनलाइन की तुलना में उपलब्धियों और अनुभवों पर प्रस्तुतियां दी गईं। उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, पीएजी, कर्नाटक, डीएलएफए, आंध्र प्रदेश की भागीदारी के साथ 'पंचायत लेखा परीक्षा की प्रभावशीलता में सुधार' पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई थी।

3. माननीय पंचायती राज मंत्री ने सचिव, पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों के पंचायती राज विभाग, एनआईआरडीपीआर, डेप्यूटी कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, निर्वाचित प्रतिनिधि/सरपंच और पंचायत पदाधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक **22** जून, **2021** को 'पंद्रहवें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान के उपयोग की सामाजिक अंकेक्षण के लिए दिशानिर्देश' जारी किए। कर्नाटक, केरल और झारखंड राज्यों के पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने चौदहवें वित्त आयोग अनुदान आदि के उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों / गतिविधियों की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने संबंधी अपने अनुभव पर प्रस्तुतीकरण दिया। झारखंड की ग्राम पंचायतों के दो सरपंचों ने राज्य के ग्राम पंचायतों में चौदहवें वित्त आयोग गतिविधियों के लिए आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षा के अपने अनुभव और लाभों को साझा किया। सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी, अनुभव और सूचना साझा करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आरएलबी / टीएलबी के सभी स्तरों द्वारा किए गए विभिन्न अनिवार्य गतिविधियों के लिए राज्यों के सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों (एसएयू) आदि द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण समुदाय

से, जहां संभव हो, मनरेगा कार्यों/गतिविधियों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के साथ पन्द्रहवें वित्त आयोग के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

4. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के लिए आरजीएसए की योजना के तहत **50.03** करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

5. इस मंत्रालय ने डॉ. एस.एस. मीनाक्षी सुंदरम, पूर्व सचिव (ग्रामीण विकास) और अध्यक्ष सलाहकार, एनआईएएस, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर की अध्यक्षता में 'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण' की जांच/समीक्षा करने और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश, **2021**' के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया। आईएमसी के अन्य सदस्य डॉ. एन. श्रीधरन, निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल (एमपी), पंचायती राज के प्रभारी सलाहकार, नीति आयोग; संयुक्त सचिव (ए, एल एवं ई) शहरी नियोजन के प्रभारी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय; रुर्बन मिशन के प्रभारी संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री के.एस. सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय हैं। आईएमसी **30** जुलाई, **2021** से पहले अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

6. पंचायतों के लिए एक मॉडल सिटीजन चार्टर माननीय केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज द्वारा दिनांक 04 जून, 2021 को जारी किया गया था। यह सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति संगठन (पंचायत) की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करेगा। यह सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ व्यवहार करते समय एक नागरिक को दिन-ब-दिन आने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा।

7. स्वामित्व स्कीम का उद्देश्य गाँवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गाँव के गृह मालिकों को 'अधिकारों का अभिलेख' प्रदान करना और संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर योजना के राष्ट्रीय रोल आउट का शुभारंभ करने के बाद, 23 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा चल रही है। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, डीजीसीए और जीईएम एक सेवा / आउटसोर्सिंग मॉडल के

रूप में ड्रोन की स्थापना की दिशा में काम कर रहे हैं। मंत्रालय विस्तृत जिलेवार ड्रोन उड़ान कार्यक्रम को तैयार करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है। अब तक 46,803 गांवों और 37 जिलों में ड्रोन उड़ान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

8. एक उपाय के रूप में पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का सख्ती से अनुसरण करता रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों से प्रयास करता रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए, 92% ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं और 83% ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक पुस्तकें बंद कर दी हैं।

9. 2,16,125 ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) पर आ चुकी हैं। जून माह 2021 में 63,413 पंचायती राज संस्थाओं ने XVवें वित्त आयोग अनुदान के व्यय के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करते हुए ऑनलाइन लेनदेन किया है।

10. पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज में रसीदों की प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 21 राज्यों ने राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है।

11. साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए; मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक एप्लिकेशन - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाह्य ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 26 राज्यों (केरल सहित) ने लेखा परीक्षकों का पंजीकरण (6,684 लेखा परीक्षक पंजीकृत) और 14वें वित्त आयोग के खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा योजना (1,09,391 ग्राम पंचायतों) की तैयारी शुरू कर दी है। 26 राज्यों ने ग्राम पंचायत (ऑडिटी) उपयोगकर्ता (2,12,495 ऑडिटी) बनाना शुरू कर दिया है। 24 राज्यों ने भी एप्लिकेशन पर टिप्पणियों (7,24,952 टिप्पणियां) को दर्ज किया है और 22

राज्यों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट (59,212 रिपोर्ट) तैयार की है। वर्ष 2020-21 के लिए 19,959 ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है।

12. मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 मनाया गया। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 के पालन के लिए राज्यों के माध्यम से और बल्क एसएमएस के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के बीच व्यापक प्रचार किया गया।

13. 1 जून, 2021 तक मंत्रालय के पास 41 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और जून माह के दौरान 259 (अर्थात 249 ऑनलाइन + 10 वास्तविक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 300 (जून में प्राप्त 259 + पिछले महीने से 41 अग्रेषित) में से 252 शिकायतों / याचिकाओं का निपटारा जून में किया गया और 48 को 1 जुलाई, 2021 तक आगे बढ़ाया गया।

14. जून 2021 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 98 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of June, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realize the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. Secretary, Ministry of Panchayati Raj and Secretary, Ministry of Rural Development through a virtual function on 18th June, 2021 jointly launched online dashboard for availability of real-time data/information regarding Covid-related measures being undertaken in rural areas and to ensure effective Covid management there. The dashboard captures several Key Performance Indicators (KPIs) for Covid containment, awareness and treatment measures being taken by the Rural Local Bodies such as Gram Panchayats (GPs) with Village Health Sanitation & Nutrition Committee (VHSNC), GPs taking up IEC activities on Covid awareness, Volunteers enrolled, Frontline workers enrolled, GPs with Isolation Centers etc. This dashboard will be a crucial resource for Central/State Government and PRIs for planning localized policy interventions and ensure optimization of critical resource interventions required in the fight against the pandemic in the rural areas. During the function, States of Bihar,

Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh and Maharashtra made presentations regarding various initiatives being taken by them as relief measures and for containment and management of Covid Pandemic in rural areas with the utilization of Central Finance Commissions' Grants for RLBs, Central/State funds etc. The States welcomed the launch of the Covid Dashboard by MoPR, and particularly highlighted and appreciated the provisions of Central Finance Commission Grants made by the Central Government for utilization by RLBs in fighting against Covid Pandemic in rural areas.

2. To discuss the various aspects and achievements regarding implementation of AuditOnline by the States till date, an interactive virtual Conference cum Review Meeting was held on 22.06.2021 under the chairmanship of Shri R.G. Viswanathan, Deputy Comptroller and Auditor General. The Conference was attended by the senior officers from Ministry of Panchayati Raj, States' Panchayati Raj Departments/States' Finance Departments, officials from AGs/PAGs across States, Local Fund Audit etc. During the conference, presentations on the achievements and experiences vis-a-vis AuditOnline were made by the lead States– Telangana, Madhya Pradesh, Bihar and Gujarat. A Panel discussion on 'Improving Efficacy of Panchayat Audit' was also held with participation of Dy. CAG, Joint Secretary, Department of Expenditure, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj, PAG, Karnataka, DLFA, Andhra, Pradesh.

3. The Hon'ble Minister of Panchayat Raj released 'Guidelines for Social Audit of Fifteenth Finance Commission (XV FC) Grants Utilization by Rural Local Bodies' virtually on 22nd June, 2021 in the presence of Secretary, Panchayati Raj, senior officers of Ministry of Panchayati Raj, States' Panchayati Raj Departments, NIRDPR, Deputy Comptroller General of India, Local Audit Departments/Local Fund Audits, elected representatives/Sarpanchs and Panchayat functionaries. Senior Officers from States' Panchayati Raj Departments of Karnataka, Kerala and Jharkhand made presentations on their experience of conducting Social Audits of works/activities undertaken in rural areas with the utilization of Fourteenth Finance Commission (XIV FC) grants etc. Two Sarpanchs of Gram Panchayats (GPs) from Jharkhand shared their experiences and benefits of Social Audit which were conducted for XIV FC

activities in the GPs of the State. The Social Audit Guidelines will ensure systematic conduct of Social Audits by Social Audit Units (SAUs) etc of States for various mandated activities undertaken by all tiers of RLBs/TLBs out of XV FC Grants etc in rural areas with the participation, experience and information sharing from the rural community. Where feasible, the Social Audits for XV FC will be conducted along with the social audit for MGNREGS works/activities.

4. Funds to the tune of Rs.50.03 Cr have been released under the scheme of RGSA towards the approved Annual Action Plan (AAP) of the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

5. The Ministry constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) chaired by Dr. S. S. Meenakshisundaram, former Secretary (RD) and Chairman Advisor, NIAS, Indian Institute of Science (1ISc), Bangalore, to examine/review the 'Rural Area Development Plan Formulation and Implementation (RADPFI) Guidelines, 2021'. Other members of IMC are Dr. N. Sridharan, Director, School of Planning & Architecture, Bhopal (MP); Advisor in-charge of Panchayati Raj , NITI Aayog; Joint Secretary (A, L&E) incharge of Urban Planning, Ministry of Housing & Urban Affairs; Joint Secretary in-charge of Rurban Mission, Ministry of Rural Development; Shri K. S. Sethi, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj. The IMC will submit their report/recommendations before 30th July, 2021.

6. A model Citizen Charter for the Panchayats was released by the Hon'ble Union Minister, Panchayati Raj, on 04th June, 2021. This would represent the commitment of the Organisation (Panchayat) towards standard, quality and time frame of service delivery, grievance redress mechanism, transparency and accountability. It would help in addressing the problems which a citizen meets, day in and day out, while dealing with the Local Governments for accessing public services.

7. SVAMITVA Scheme aiming to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property

cards to the Property owners. After Hon'ble Prime Minister launched the National roll out of Scheme on National Panchayati Raj Day, 24th April 2021, 23 States/UTs have signed memorandum of understanding with the Survey of India for the implementation of Scheme and discussions are on-going with other States for signing of MoU. To boost Drone ecosystem and achieve Scheme targets, Department of Science and Technology, SoI, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defence, Drone Federation of India, DGCA and GeM are working towards establishment of Drone as a service/ outsourcing model. Ministry is continuously engaging with States/UTs to prepare detailed district- wise drone flying schedule. Till now, drone flying has been completed in 46,803 villages and completed in 37 districts.

8. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2020-21, 92% of the GPs have closed their month books and 83% of the GPs have closed their year books.

9. 2,16,125 GPs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of June 2021- 63,413 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

10. MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 21 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

11. Also, for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 26 (including Kerala) State have started registration of Auditors (6,684 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 1,09,391 GPs) for Auditing 14th Finance Commission

accounts. 26 States have started creating GP (Auditee) users (2,12,495 Auditees). 24 States have also recorded Observations (7,24,952 observations) on the application and 22 States have generated audit reports (59,212 Reports). For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 19,959 GPs.

12. International Day of Yoga-2021 was observed in the Ministry. Also, wide publicity among the PRIs through the States and through bulk SMSes were given for observance of International Day of Yoga-2021 at the PRI level.

13. There were 41 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st June, 2021 and 259 (i.e. 249 online + 10 physical) grievances/ petitions were received during the month of June. Out of total 300 (259 received in June + 41 carried forward from last month), 252 grievances/petitions were disposed in June and 48 were carried forward as on 1st July, 2021.

14. During June 2021, 98 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****